श्री संजय निरुपम : यह नैट प्रॉफिट नहीं है जो आप बता रहे हैं। नैट प्रॉफिट दूसरी चीज होती है। टैक्स देने के बाद और डिविडेंड देने के बाद प्रॉफिट क्या है ? यह जो पब्लिक सैक्टर की रिव्यू बुक है, मैं उसकी रिपोर्ट बता रहा हूं कि टैक्स पेमेंट के बाद नैट प्रॉफिट कितना है। मैं आपको नैट प्रॉफिट बता रहा हूं, आप जाकर बुक देख लीजिएगा, यह 1997-98 में 401 करोड़ रुपए है, उसके बाद 1998-99 में 258 करोड़ रुपए है, 1999-2000 में 276 करोड़ रुपए है। मैं सदन में यह जानकारी दे रहा हूं, आप जाकर इसे क्रॉस-चैक कर सकते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : जैसा मैंने कहा कि इस बार नैट प्रॉफिट 491 करोड़ रुपए है जिसमें 395 करोड़ रुपए का ऐरियर दिया गया है। हम ऐरियर देने के बाद और टैक्स देने के बाद की फिगर बता रहे हैं। उसमें ऐरियर का प्रावधान था और वह मजदूरों को मिलना था। इस ऐरियर का प्रावधान पहले नहीं किया गया था जिसके लिए मजदूर यूनियनों का हम पर काफी दबाव रहता है और हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए हमने प्रॉफिट के अंदर ऐरियर का प्रावधान किया। मैं एक के बाद एक करके आपको बता दूं ताकि इसमें कोई गलतफहमी न रहे। इसमें ऐरियर 395 करोड़ रुपए है, ग्रेच्युटी 68 करोड़ रुपए है और कर देने के पश्चात लाभ 28.23 करोड़ रुपए है। मैं इसको फिर से पढ़ देता हूं टैक्स देकर जो लाभ है वह 28.23 करोड़ रुपए है और टोटल लाभ 491 करोड़ रुपए है।

श्री संजय निरुपम : सर, कोयले के कारोबार के बारे में नहीं बताया है।...

MR. CHAIRMAN : It is finished now. Next question. Mr. Rajnath Singh 'Surya'.

Solar Lantern

*523. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA' : †
MISS FRIDA TOPNO :

Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the solar lantern could be a better substitute of electricity for lighting purpose particularly in rural, backward, hilly and far-flung areas;

(b) if so, what steps Government are taking to popularise and provide this lantern in the above areas:

(c) whether Government propose to launch any Centrally sponsored programme for the purpose in Bihar, Uttar Pradesh and Uttaranchal; and

(d) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

†The Question was actually asked on the floor of the house by Shri Rajnath Singh 'Surya'

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI M. KANNAPPAN) . (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Solar lanterns were developed as a substitute for kerosene lanterns. They have been found to be very useful in rural and far-flung areas because of unreliable or total lack of power supply. In order to promote the use of solar lanterns in such areas, Government is implementing a countrywide programme for the supply of such lanterns on a subsidized basis. The subsidy is provided to non-commercial users of solar lanterns. For the current year, the admissible central subsidy per lantern is Rs. 1,300. For the North Eastern Region, the subsidy is 90% ex-works cost of the lantern subject to a maximum of Rs. 3,000. Other support measures taken by Government include reduction in customs duties on imported materials, exemption from excise duty and provision of loan assistance to manufacturers, intermediaries and non-government organizations for promotion of solar lanterns.

(c) The solar lantern programme is also being implemented in the states of Bihar, Uttar Pradesh and Uttaranchal. 42,149 solar lanterns have been distributed in Bihar (including Jharkhand) and 67,313 in Uttar Pradesh (including Uttaranchal) upto 31st March 2001. The following quantities have been allocated to these states for the year 2001-02 :

State	*Solar Lanterns*
Bihar	8,000
Uttar Pradesh	10,000
Uttaranchal	4,500

(d) Does not arise.

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसका जो पहला भाग है, उसमें उन्होंने कहा है कि विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय नहीं है और सब जगह पर नहीं है इसलिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने योजना बनाई है और सभी राज्यों में यह योजना चलाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि इसके लिए अन्य राज्यों में 1,300 रुपये प्रति लालटेन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अधिकतम 3,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सब्सिडी की कुल मद में बजट का कितना प्रावधान किया गया है ?

SHRI M. KANNAPPAN : Sir, solar lanterns, solar home-lighting systems, solar street-lighting systems, solar power plants and other such systems are all eligible for subsidy.

श्री राजनाथ सिंह ''सूर्य'' : सर, यह तो मंत्री जी ने कहा ही है। हम यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है ? सारे देश के लिए इसमें कितने धन का प्रावधान किया गया है ?

SHRI M. KANNAPPAN : Sir, the Budget provisions are different for various States.

श्री राजनाथ सिंह ''सूर्य'' : सभापति महोदय, प्रश्न के दूसरे भाग में माननीय मंत्री जी ने तीन राज्यों के बारे में बताया है कि बिहार में 8,000, उत्तर प्रदेश में 10000 और उत्तरांचल में 4,500 सौर लालटेन देने की योजना बनाई गई है। इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो मुश्किल से 10 लाख, 15 लाख और लगभग 5 लाख रुपये का प्रावधान इन राज्यों के लिए किया गया है। विद्युत का जिस प्रकार का अभाव है और हमारे यहां जितना सौर ऊर्जा उपलब्ध है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रावधान बहुत ही कम है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रावधान को इतना सीमित करने का क्या कारण है ? क्या राज्यों से ही इतनी डिमांड आई है या भारत सरकार अपने संसाधनों को देखकर यह विचार कर रही है इसको बढ़ाने की दृष्टि से क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। जैसा कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि बिजली की आपूर्ति सब जगह सम्भव नहीं है और हमारे यहां सौर ऊर्जा इतनी मात्रा में उपलब्ध है जिसका बहुत उपयोग करते हैं। एक सौर चूल्हा पहले दिया जाता था, उसका भी हमने पता किया तो वह भी मिलता नहीं है। आपने बताया कि उस पर सब्सिडी मिलती है। जब मैंने उसको लेने के लिए पता किया तो पता चला कि अब सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इसकी कम मात्रा निर्धारित करने का क्या कारण है ? क्या आप इसको स्पष्ट करेंगे ?

SHRI M. KANNAPPAN : In the Ninth Plan, the target was 3,00,000 solar lanterns, 2,00,000 solar home-lighting systems, 1,600 power plants and other systems. The total Budget provision is Rs. 290 crores. These are the details.

कुमारी फ्रिडा टोपनो : सभापति महोदय, मिनिस्टर साहब ने उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल के आंकड़े दिए हैं। लेकिन और भी बहुत से स्टेट्स हैं, जो पहाड़ी अंचल है जहां पर इलैक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती है, विशेषकर के पहाड़ी अंचल में, जहां पर बहुत बड़े जंगल हैं, वहां पर लाइन डालना भी मुश्किल होता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उड़ीसा से सोलर लालटेन के प्रोवीज़न के लिए कुछ प्रपोजल्स मिनिस्टर साहब के पास आए हैं ? वहां पर बहुत से ऐसे जिले हैं - कोरापुट है, कालाहांडी है, सुंदरगढ़ है - ऐसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, जहां इलैक्ट्रिक लाइन भी नहीं जा सकती है इसलिए सभापति महोदय के जरिए मेरा

आपसे निवेदन है कि सुंदरगढ़ को भी वहां आइडैंटीफाई किया जाए और इनसैंटिव प्रोग्राम वहां किया जाए जिससे कि सोलर लालटेन हाइली सब्सीडाइज्ड और एफोर्डेबल रेट्स पर बहुतायत से वहां उपलब्ध किया जा सके। इसके बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं ?

SHRI M. KANNAPPAN : Mr. Chairman, Sir, as regards the supply of solar lantern, there are about 18,000 villages in the remote and difficult areas of the country, where it is not economically viable to provide electricity through the conventional grid expansion programme. A new programme is sought to be launched for electrification of such villages through renewable energy options. This challenging task is to be completed by the end of the Eleventh Five-Year Plan. The programme is likely to be supported through a Central grant of 90 per cent. Capital investment is needed for setting up such projects. The balance 10 per cent capital and funds required for O&M are to be met by the States, the promoters and the beneficiaries. The programme is awaiting the approval of the Government. So, these are the programmes for electrification of remote rural areas.

SHRI RAJIV SHUKLA : Sir, India has got sunlight in abundance. Some programmes had been launched during Shri Narasimha Rao's regime to exploit sunlight for non-conventional energy purposes. I would like to know from the Minister whether those programmes are continuing for R&D purposes and also for other purposes.

SHRI M. KANNAPPAN : Mr. Chairman, Sir, all other schemes are continuing, except the solar lantern. My Ministry is also implementing programmes like solar home-lighting system, solar street-lighting system, solar power plants and solar bunds. In addition to this, there are solar water heating systems, solar cookers. All these schemes are eligible for soft loans, at a concessional rate of interest.

MISS MABEL REBELLO : Sir, I am told that we have, in seven States of our country, an UNDP-supported programme to popularise the solar lantern. I would like to know from the hon. Minister which are those seven States, when was this programme started, what is the funding pattern, are they giving them technological support, by way of latest technology, so that they could develop the latest solar lantern? I also want to know from the hon. Minister, when it was started and when it is going to end. What is the total programme, in this regard?

SHRI M. KANNAPPAN : Sir, this supplementary is about the UNDP-supported programme. As this supplementary does not arise from the main question, the hon. Member should put a separate question.

PROF. M. SANKARALINGAM : Sir, solar lantern is one of the forms of utility of solar energy. Solar energy can be utilised for different purposes, like heating water, accelerating motor cars, etc. What are the detailed programmes? I want to know from the hon. Minister about the incentives being given by the Central and the State Governments in this regard.

SHRI M. KANNAPPAN : Sir, in the written answer, I have already mentioned about the items and the subsidies and inter-subsidies on them.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Sir, the hon. Minister has given some figure about the subsidies for the solar lantern in the North-East region and in certain other areas. One of the major problems, when these programmes are launched, is that, a substantial amount is to be invested on research work because this is a sector where the industrialised countries, especially the West, are not interested as they don't have adequate sunlight. On the other hand, we have this source in abundance. So, would the hon. Minister enlighten the House whether the Government is going to spend more money on basic research in this sector so that the cost of these items, which the hon. Minister has referred to, is reduced ? The hon. Minister has stated that Rs. 1,300 is provided as subsidy for the solar lantern. I would like to know what is the actual cost of manufacturing, against which this Rs. 1,300 is being provided as subsidy ?

SHRI M. KANNAPPAN : Sir, actually, its cost ranges from Rs. 3,000 to Rs. 5,000 per lantern. The Central subsidy is Rs. 1,300.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Would you please explain the rationale as to why there is so much variance ? Somewhere you can produce it at Rs. 3,000; and at another place, it is Rs. 5,000. Forget about the North-Eastern areas where you are providing Rs. 3,000. I am talking about the subsidy of Rs. 1,300. What is the actual average cost ? Why does it vary between Rs. 3,000 and Rs. 5,000 ?

SHRI M. KANNAPPAN : The present price ranges from Rs. 3,000 to Rs. 5,000, depending on the make, model, quality and place of supply. But the Central subsidy is Rs. 1,300 on that. In the North-Eastern region, including Sikkim, it is 90% of the cost of the solar lantern, subject to a minimum of Rs. 3,000.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Are you going to give any money for research ?

प्रो. रामदेव भंडारी : मान्यवर, देश में बिजली की भारी कमी है और इस परिप्रेक्ष्य में सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करें, इस दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश

और बिहार आबादी के दृष्टिकोण से दो सबसे बड़े राज्य हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार बिहार में 31 मार्च, 2001 तक 42,149 और उत्तर प्रदेश में 67,313 सौर लालटेनों का वितरण किया जा चुका है और इस वर्ष 2001-2002 में आठ हजार बिहार में, दस हजार उत्तर प्रदेश में और 4500 उत्तरांचल मे वितरण हुआ है। महोदय, दूरदराज के गांवों में जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, उन गांवों के लिए सौर लालटेन बहुत उपयोगी है, इस संबंध में अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है। मेरा अनुभव यह है कि अभी भी यह लालटेन गरीबों के बीच में या कम आय वाले लोगों के बीच में नहीं जा रही है। मुझे इसके दो कारण लगते हैं, एक कारण आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने बताया कि 1300 रुपए सब्सिडी है। जो कम आमदनी वाले गरीब लोग हैं वे 1300 रुपए की सब्सिडी भी नहीं दे सकते। तीन हजार दाम है अगर इसमें 1300 हटा दिया जाए तो 1700 तब भी रह जाता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए लोगों को जागृत करने के लिए सरकार के पास कोई कार्यक्रम है ? दूसरी बात यह है कि इसकी सब्सिडी और बढ़ाई जाए ताकि दाम कम लगे और दूरदराज के गांवों में कम आय वाले गरीब लोग भी इसको खरीद सकें। मैं इस संबंध में जानकारी चाहता हूं ?

SHRI M. KANNAPPAN : Mr. Chairman, Sir, in addition to the subsidy, the Government gives so many concessions such as reduction in custom duty on key materials, exemption from excise duty, expansion of market leading to the increased production at lower cost. ... *(Interruptions)* ...

प्रो. रामदेव भंडारी : यह सब सवाल के जवाब में लिखा हुआ है। आपने जो जवाब दिया है उसमें यह सब लिखा हुआ है। मेरा सवाल सब्सिडी बढ़ाने से है।

SHRI M. KANNAPPAN : Sir, due to these measures, the price of lantern has been brought down to Rs. 3000 in 2001 from Rs. 5000 in 1993. The concessions are being given by the Government. However, the suggestions given by the hon. Member will be taken into consideration.

Replacement of 'EAS' by 'Food for Work' programme

*524. SHRI K. KALAVENKATA RAO : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Government propose to replace the 'Employment Assurance Scheme' (EAS) by 'Food for Work' programme to ensure that there is no starvation;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?